महिला तथा बाल विकास विभाग

दिनांक 5 जुलाई, 2011

संख्या १४७१/एस०डब्ल्यू०(3)/2011.—बाह विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (2007 का 6), की धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम हरियाणा बाल विवाह प्रतिषेध नियम, 2011 कहे जा सकते हैं।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ;
 'अधिनियम' से अभिप्राय है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (2007 का 6) ;

परिभाषाएं।

- (2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो क्रमशः अधिनियम में उन्हें दिया गया है।
 - बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी :

बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के कर्त्तव्य। धारा 16

- (क) बाल विवाह के विरुद्ध सामाजिक जागरुकता सृजित करेगा ;
- (ख) अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों का प्रकाशन तथा व्यापक प्रचार करेगा ;
- (ग) बच्चों के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करने के लिए बाल विवाह से सम्बन्धित सभी शिकायतों/ जानकारी की समीक्षा करेगा;
- (घ) कोई अन्य कार्रवाई करेगा जो बाल विवाह के प्रतिषेध हेतु आवश्यक हो ; तथा
- (ङ) बाल विवाह के बंधन में आने वाली कन्या संविदा करने वाले पक्षकार के पैतृक घर या दैकल्पिक निवास का मानीटर करेगा।
- 4. पूर्वागामी कर्त्तव्यों के होते हुए भी, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी जैसे आखा तीज, अक्षय तृतीया, महाशिवरात्रि इत्यादि अवसरों पर सामूहिक बाल विवाहों के अनुष्ठान के दौरान निम्नलिखित कृत्य करेगा; अर्थात् कथित

बाल-विवाह के सामूहिक अनुष्ठान को रोकने के उपाय। धारा 13

- (क) एक दूसरे के बीच अच्छा समन्वय सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी बाल विवाह का अनुष्ठान न हो, सभी संबंधित विभाग जैसे सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, महिला तथा बाल विकास, पुलिस, सूचना तथा लोक सम्पर्क, राजस्व इत्यादि को शामिल करेगा:
- (ख) बाल विवाह के विरुद्ध नियमित जागरुकता अभियान चलाने के साथ-साथ सामूहिक बाल विवाह के अनुष्ठान के लिये नियत तिथि से पूर्व कम से कम एक मास पहले योजना तथा नीतिगत योजना आरंभ करेगा:
- (ग) बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में स्थानीय भाषा में व्यापक प्रचार करेगा और इसके लिए फिल्मों, विज्ञापनपट्ट, पोस्टर, पंफलैट्स, लाउडस्पीकर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों इत्यादि द्वारा तथा टेलिविजन, रेडियो, समाचार-पत्रों तथा बसों तथा रेलगाड़ियों पर विज्ञापन जैसे रचनात्मक और जन माध्यम का प्रयोग करेगा।
- (घ) बाल विवाह के किसी तरह की टिप्पणी या गुणगान के साधन को गंभीरता से लेगा तथा ऐसे गुणगान के लिए उत्तरदायी ऐसे व्यक्तियों/संगठनों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही सहित उचित कदम उठाएगा;
- (ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारी तथा व्यवसायिक जैसे डाक्टर इत्यादि किसी भी तरह से झूठा चिकित्सा प्रमाण-पत्र/ जन्म/आयु प्रमाण-पत्र जारी न करें तथा यदि वह ऐसा करते पाये जायें, तो उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही करेगा:
- (च) यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाल विवाह के अनुष्ठान न किये जायें अपने अधिकार क्षेत्र में नियमित रूप से सभी पुजारियों के साथ समन्वय करेगा तथा मानीटर करेगा।
- (छ) सामुदायिक केन्द्र, सार्वजनिक भवन, बैंकट हाल, मैरिज पैलेस इत्यादि के मालिकों अथवा प्रभारी व्यक्तियों को बाल विवाहों के अनुष्ठान की रोकथाम करने हेतु शिक्षित/सम्मिलित करेगा।

शकुन्तला जाखू, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, महिला तथा बाल विकास विभाग।

WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT

The 5th July, 2011

No. 177/SW(3)/2011.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 19 of the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (6 of 2007), the Governor of Haryana hereby makes the following rules, namely:—

Short title and Commencement.

- . (i) These rules may be called the Haryana Prohibition of Child Marriage Rules, 2011.
 - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions.

- 2. (i) In these rules, unless the context otherwise requires,—
 "Act" means the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (6 of 2007).
 - (ii) The words and expressions used in thse rules but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the act.

Duties of Child Marriage Prohibition Officer. Section 16

- 3. The Child Marriage Prohibition Officer shall,—
 - (a) creat social awareness against child marriage;
 - (b) cause the publication and wide circulation of the Act and the rules;
 - (c) follow-up all complaints/information related to child marriage to ensure the best interest of the child;
 - (d) take any other action, which is necessary for prohibition of child marriage; and
 - (e) Monitor the parental home or alternative residence of female contracting party to child marriage.

Measures to prevent mass solemnization of child marriages.

- 4. Notwithstanding the foregoing duties, the Child Marriage Prohibition Officer shall during the mass solemnization of child marriages on occasions such as Akkha Teej, Akshaya Tritiya, Mahashivaratri etc. perform the following functions, namely:—
 - (a) involve all the related departments such as Social Justice and Empowerment, Health, Education, Rural Development, Panchayati Raj, Women and Child Development, Police, Information and Public Relations, Revenue etc. among others for better co-ordination to ensure that no child marriages are solemnized;
 - (b) being planning and strategizing for at least a minimum of one month coupled before the date fixed for mass solemnization of child marriage, with constant awareness drive against child marriage;
 - (c) give wide publicity about the consequence of child marriage in the local language and use creative and mass awareness through films, hoardings, posters, pamphlets, loudspeakers, cultural programmes etc. and advertisements on the television, radio, newspapers and on buses and trains;
 - (d) take a serious note of any form or means of glorification of child marriage and shall initiate appropriate measures, including legal action, against such persons/organizations responsible for such glorification;
 - (e) ensure that Officials and Professionals like doctors etc. on no account issue false medical/birth/age certificates and initiate appropriate action when they are found doing so;
 - (f) coordinate with and monitor all priests in their jurisdiction regularly to ensure that the child marriage shall not be solemnized;
 - (g) educate/involve the owner or person in-charge of Community Centre, Public Building, Banquet Hall, Marriage Palace etc. for the prevention of solemnization of child marriage.

SHAKUNTLA JAKHU,
Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government Haryana,
Women and Child Development Department.